प्रेषक,

एस. राजू प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

रावा मं,

1. निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड। देहरादून।

2. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 25 जून, 2013

विषय:- राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पुत्री के विवाह हेतु तथा बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना में संशोधन। महोदय.

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5274/26-3-97-4(188)/93 25.10.1997 तथा शासन संख्या—1030/XVII-1/2011—01(98)2011 दिनांक 12.12.2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेशों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन एवं असाहय व्यक्तियों को ईलाज हेतु रूपये 2,000/- की आर्थिक सहायता तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूपये 15,000 / –वार्षिक आय सीमा वाले अथवा बी.पी.एल. परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रूपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में उक्त योजना में संशोधन कर निम्न व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

(1) पुत्रियों की विवाह हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

(2) सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रूपये 50,000/-(रूपये

पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

(3) बीमारी के ईलाज हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा रूपये 15,000 / - (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक अथवा बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्धित हों, को आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 10,000 / -(रूपये दस हजार मात्र) तक (यथास्थिति बीमारी के स्वरूपानुसार) की धनराशि प्रदान की जाएगी।

योजना से सम्बन्धित शेष शर्ते पूर्व की भांति यथावत रहेगी। 4.

भवदीय

(एस. राजू) प्रमुख सचिव संख्या- 1919 (1)/XVII-1/2013-01(98)/2011, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2. निजी सचिव-मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।

3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग / नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय।

8. गार्ड फाईल

आ्जा, से,

- (एस.एस. वल्दिया) संयुक्त सचिव।

0